MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him give notice. ...*(Interruptions)*... He can give a notice. ...*(Interruptions)*...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश) : सर, नोटिस दिया हुआ है। ...(**व्यवधान**)...सर, अंसारी साहब ने नोटिस दिया हुआ है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will be examined. ...*(Interruptions)*... मैं नोटिस को एग्जामिन करूंगा। ...(**व्यवधान**)...नोटिस एग्जामिन करूंगा। श्री सालिम अन्सारी।

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Situation arising out of acquittal of accused persons in Hashimpura mass killing case in U.P.

श्री सालिम अन्सारी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं देश के सबसे बड़े सदन में एक ऐसे दिल दहलाने वाले मामले को उठाना चाहता हूं, जो आज़ाद हिन्दुस्तान में अक़्लियतों के साथ होने वाली सबसे बड़ा घटना है, जिसमें लोकतंत्र के चारों स्तम्भ हिल गए। आज़ाद हिन्दुस्तान में पुलिस हिरासत में कत्ल के सबसे बड़े जघन्य अपराध, हाशिमपुरा हत्याकांड में PAC द्वारा 42 मुस्लिम नौजवानों की हत्या के बाद उनके शव मुरादनगर के नजदीक गंगनहर में, यू.पी. दिल्ली के बॉर्डर पर हिंडन नदी में फेंक देने के मामले में 28 साल बाद, PAC के 16 मुल्ज़िमों को दिल्ली की एक अदालत ने सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। 28 साल चले इस मुकदमे पर समूचे देश की निगाहें टिकी हुई थीं और नरसंहार में मारे गए लोगों के परिवार वालों को इंसाफ की उम्मीदें लगी हुई थीं, परंतु उन्हें निराशा हुई। हालांकि इस कत्लेआम में शामिल पुलिस वालों को, पीएसी को सज़ा मिलनी चाहिए थी, ताकि भविष्य में फिर कोई खाकी वर्दी शैतान ऐसा न कर सके। महोदय, यह बहुत ही अहम मामला है और इस मामले में बड़े-बड़े लोग शामिल रहे हैं।

उपसभापति महोदय, मेरठ में फसाद का सिलसिला 14 अप्रैल, 1987 में शुरु हुआ था, जो लगभग तीन माह चला था। इस दौरान 22 मई को हाशिमपुरा और 23 मई को मलियाना में एक बड़े कत्लेआम को अंजाम दिया गया था, जिसमें सौ बेगुनाह लोग मारे गए थे। महोदय, हाशिमपुरा कत्लेआम के मामले में सीनियर पत्रकार निखिल चक्रवर्ती, कुलदीप नैयर, आई.के. गुजराल, जो बाद में देश के प्रधान मंत्री बन गए, की अगुवाई में पीयूसीएल की एक टीम बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि यह कत्लेआम ठीक वैसा ही है, जैसे नाज़ियों ने यहूदियों का कत्ल किया था। महोदय, 1994 और 2000 के बीच पीएसी के जवानों के खिलाफ, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, 23 वॉरंट जारी हुए। इसके साथ ही 1997 से लेकर 2000 तक 17 बार गैर-ज़मानती वॉरंट भी जारी किए गए, लेकिन अभियुक्त के ...(**व्यवधान**)... सन् 2000 में 16 मुलज़िमों ने सरेंडर कर दिया और जल्द ही उन्हें ज़मानत पर छोड़ दिया गया। ...(**व्यवधान**)... उनको बरी कर दिया गया, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। 7 मई को विभिन्न दलों के सांसदों ने संसद के बाहर गांधी जी की मूर्ति के सामने धरना दिया ताकि जघन्य अपराध करने वालों को सज़ा मिल सके। अतः मेरी मांग है कि ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time over; time over.

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) : महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : महोदय, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार) : महोदय, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार) : सर, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करती हूं।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र) : सर, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूं।

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं भी इस विषय के साथ एसोसिएट करती हूं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (उत्तराखंड) : महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI VIVEK GUPTA (West Bengal): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SANTIUSE KUJUR (Assam): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

PROF. JOGEN CHOWDHURY (West Bengal): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ISHWARLAL SHANKARLAL JAIN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI MAJEED MEMON (Maharasthra): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHUPINDER SINGH (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we too associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. The names of all the Members who are associating may be noted. ...*(Interruptions)*... All your names will be recorded. Now, Shri Sukhendu Sekhar Roy.

Request to Withdraw Home Ministry's order dated 23rd July, 2014, Restricting Jurisdiction of Anti-Corruption Bureau

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, the Anti-Corruption Branch of the Government of Delhi is a notified Police Station for the purpose of registration of FIR and investigation of offences covered under the Prevention of Corruption Act, 1988. The Branch has been in existence for almost half-a-century, and the officers of the Branch were authorized to investigate the offences under the erstwhile Prevention of Corruption Act, 1947 *vide* notification dated 21st March, 1968. They were authorized to make arrests and the Branch was declared as a Police Station for offences recorded for illegal gratification in 1975. The Anti-Corruption Branch functions under the overall supervision and control of the Director of Vigilance of the Government of NCT of Delhi.

During the 49 days of Aam Admi Party Government, the Anti-Corruption Branch of Delhi Government was revitalized and an Anti-Corruption helpline was launched to facilitate the citizens who wanted to report incidents of corruption in public life. The citizens of Delhi responded enthusiastically to this initiative and complaints poured in against different authorities including officials of the Delhi Police, DDA, Municipal Corporations and the Central Government besides various Departments of the Government of the NCT of Delhi and also a few former Ministers and corporate honchos. Thereafter, a notification dated 23rd July, 2014 was issued, surprisingly, by the Ministry of Home Affairs, Government of India, restricting the jurisdiction of the Anti-Corruption Branch of the Government of the NCT of Delhi over the officers and employees of the Government of NCT of Delhi. Now, Sir, this has created problems for the administration of Delhi Government to go against the corrupt officials. Now, Sir, this notification, apart from being against the constitutional provisions of Article 239AA, is also attempting to limit the powers of a popularly-elected Government. This is highly unconstitutional and against the principles of federalism. If the Central Government is serious about introducing reforms in administration and wants to bring about a positive and forward